बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 140 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 17 मार्च 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

कांग्रेस का बड़ा आरोप- ट्रंप और नेतन्याहू के चक्कर में भारत कम कर रहा है ब्रिक्स+ में नेतृत्व का मौका!

नई दिल्ली । कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखने और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ करीबी संबंध बनाए रखने की लालसा में ब्रिक्स+ अध्यक्षता के महत्व और उसकी प्रतिष्ठा को कम कर रहे हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि ब्रिक्स+ की अध्यक्षता करते हुए भारत, पश्चिम एशिया संकट पर कोई सामूहिक बयान जारी नहीं कर पाया है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, 2025 में ब्राजील ब्रिक्स+ का अध्यक्ष था। उसने जून 2025 में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों के मुद्दे पर 11 सदस्य देशों से एक संयुक्त बयान जारी करवाया था।

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, जीटीबी-कैंसर इंस्टीट्यूट और राजीव गांधी अस्पताल का होगा एकीकरण

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल (जीटीबी), दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (डीएससीआई) और राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल (आरजीएसएसएच) को एकीकृत कर एम्स की तर्ज पर एक स्वायत्त चिकित्सा संस्थान बनाने की घोषणा की है। साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (इहबास) को भविष्य में निमहंस-2 के रूप में विकसित करने की योजना पर भी काम शुरू किया जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि वे दिल्ली को चिकित्सा का बड़ा केंद्र बनाना है। सचिवालय में हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की इस विषय पर चर्चा हुई थी। इसमें दिल्ली के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों को एकीकृत कर एक मजबूत और आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों का वैज्ञानिक और प्रभावी उपयोग जरूरी है। इसके लिए अलग-अलग संस्थानों के एकीकरण से डॉक्टरों, विशेषज्ञों, उपकरणों और बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

अस्पतालों में बेड और मरीजों का दबाव घटेगा

बैठक में अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की स्थिति और मरीजों के बढ़ते दबाव पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि कुछ अस्पतालों में मरीजों का दबाव बहुत अधिक है, जबकि कुछ अस्पतालों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कुल 650 बेड की क्षमता है, लेकिन वर्तमान में करीब 250 बेड ही उपयोग में हैं और करीब 400 बेड खाली हैं। दूसरी ओर जीटीबी अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी अधिक है। यहां करीब 1400 बेड की मूल क्षमता के मुकाबले 1500 से अधिक बेड का उपयोग किया जा रहा है। मरीजों के आंकड़ों के मुताबिक जीटीबी

अस्पताल की ओपीडी में हर साल करीब 14 लाख से अधिक मरीज आते हैं और करीब 95 हजार मरीज आईपीडी सेवाएं लेते हैं। वहीं दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में करीब 1.27 लाख ओपीडी मरीज आते हैं और राजीव गांधी अस्पताल में करीब 2.87 लाख ओपीडी मरीज दर्ज किए गए हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि जीटीबी अस्पताल पर मरीजों का दबाव ज्यादा है, जबकि अन्य अस्पतालों की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।

सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं सबको मिलेंगी

मुख्यमंत्री ने बताया कि तीनों अस्पतालों के एकीकरण के बाद विभिन्न सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का सुव्यवस्थित वितरण किया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, रूमेटोलॉजी और क्लीनिकल हेमेटोलॉजी जैसी सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को कैंसर उपचार का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा, जहां रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, पेलिएटिव केयर और रेडियो इमेजिंग जैसी सेवाओं को एकीकृत किया जाएगा। वहीं गुरु तेग बहादुर अस्पताल में ऑर्थोपेडिक्स, इंटरनल मेडिसिन, ईएनटी, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी और नेत्र रोग जैसे विभागों को और मजबूत किया जाएगा।

बैठक में तय किया कि कई अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण मौजूद हैं, लेकिन विशेषज्ञ स्टाफ की कमी और संसाधनों के बिखरे होने के कारण उनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के लिए राजीव गांधी अस्पताल में उन्नत ब्रोंकोस्कोपी सुविधा उपलब्ध है, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में रेडियोथेरेपी के लिए लीनियर एक्सीलेरेटर मौजूद है,

राजीव गांधी अस्पताल में कैथ लैब और इको लैब हैं, जबकि जीटीबी अस्पताल में बोन बैंक जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार का कहना है कि एकीकृत व्यवस्था के तहत इन सभी महंगे उपकरणों का समन्वित और बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे मरीजों को अधिक प्रभावी उपचार मिल सकेगा।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा निमहंस-2

दिल्ली सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (इहबास) को बंगलूरू के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस) की तर्ज पर विकसित करने की योजना बना रही है।

इस योजना के तहत इहबास अपनी करीब 75 एकड़ खाली भूमि गुरु तेग बहादुर अस्पताल को उपलब्ध कराएगा, ताकि यहां एक विशाल एकीकृत चिकित्सा संस्थान विकसित किया जा सके। इहबास के पास कुल 111.69 एकड़ भूमि है, जिसमें से बड़ा हिस्सा अभी खाली है और भविष्य के विस्तार के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। वर्तमान में संस्थान का अस्पताल भवन करीब 19.9 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। सरकार की योजना के मुताबिक पुराने और जर्जर भवनों की जगह आधुनिक स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया जाएगा। इस परियोजना के तहत नए हॉस्टल, अत्याधुनिक लैब, पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री सुविधाएं, ऑडिटोरियम और लेक्चर थिएटर बनाए जाएंगे।

ईरान से हमारी दोस्ती- जयशंकर बोले- भारतीय झंडे वाले जहाजों को निकालने के लिए कोई समझौता नहीं, पुराना सहयोग

नई दिल्ली । पश्चिम एशिया में 17 दिन से जारी संघर्ष ने वैश्विक तेल बाजार को हिला कर रख दिया है। इसका बड़ा असर हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर देखने को मिला, जिसके चलते दुनियाभर की तेल आपूर्तियों संकट के बादल तक दिखने लगे। इसी तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारत ने कूटनीतिक कदम उठाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत ईरान के साथ सीधे और निर्णायक संवाद कर रहा है, जिससे भारतीय ध्वज के साथ जहाजों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित हो रहा है। जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरानी अधिकारियों के साथ सीधे संवाद ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। इसके तहत अभी कई और भारतीय ध्वज वाले जहाजों को होर्मुज जलमार्ग से गुजरना बाकी है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में जयशंकर ने स्पष्ट किया कि हर भारतीय जहाज को व्यक्तिगत रूप से अनुमति दी जा रही है और इसके लिए भारत और ईरान के बीच कोई नया

समझौता नहीं हुआ है। इस दौरान जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय ध्वज वाले जहाजों के सुरक्षित आवागमन के बदले ईरान को भारत की तरफ से कोई लाभ नहीं दिया गया। उनका कहना था कि भारत और ईरान के बीच पुराना सहयोग रहा है, इसी आधार पर हमने यह कदम उठाया। यह कोई लेन-देन का मामला नहीं है। बता दें कि पिछले सप्ताह ईरान ने दो भारतीय झंडाधारी एलपीजी वाहनों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी थी। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेसीयान के टेलीफोनिक संवाद के कुछ ही घंटे बाद आया, जो अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पहला संपर्क था। इसके अलावा, जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराघची के बीच भी चर्चा हुई। हालांकि ईरान ने हॉर्मुज को केवल अमेरिकी और इस्राइली जहाजों और उनके सहयोगियों के लिए के लिए बंद रखा है। होर्मुज जलमार्ग से विश्व का लगभग 20 प्रतिशत तेल गुजरता है। ऐसे में बीते 17 दिनों से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण इसके संचालन में व्यवधान आया है और फिर इस संघर्ष के चलते कच्चे तेल की कीमत 100 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि ऐसी कठिन परिस्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों से हॉर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजने का आह्वान किया है। हालांकि अधिकतर देशों से उनके इस आह्वान पर नकारात्मक संदेश ही आया है। जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सभी देशों ने होर्मुज में अपना युद्धपोत भेजने से इनकार कर दिया। ऐसे में बात अगर भारत की करें तो भारत ने अपनी रणनीति के तहत सीधे संवाद और समझौते के बजाय सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने का रास्ता अपनाया है। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत अपनी रणनीति यूरोपीय देशों के साथ साझा करने को तैयार है, लेकिन प्रत्येक देश की ईरान के साथ स्थिति अलग है।

दिल्ली रेलवे में बदमाशों की अब खैर नहीं! सरकार ने भी कसी कमर; गिरफ्तारी और मुकदमों में भारी उछाल

नई दिल्ली। राजधानी के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में नियम उल्लंघन, अव्यवस्था और ट्रैक पर अतिक्रमण जैसी समस्याओं पर लगाम कसने के लिए कार्रवाई तेज की गई है। इसके चलते पिछले एक वर्ष में रेलवे से जुड़े मामलों, गिरफ्तारियों और जुर्माने में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। RPF के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से नवंबर 2024 के बीच 26,523 मामले दर्ज किए गए थे और 24,866 लोगों को पकड़ा गया था। इन मामलों में करीब 1.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। वहीं, 2025 की समान अवधि में मामलों की संख्या बढ़कर 34,244 हो गई और 32,512 लोगों को पकड़ा गया। इस दौरान करीब 1.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। यानी मामलों में लगभग 29 प्रतिशत और पकड़े गए लोगों की संख्या में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार रेलवे ट्रैक पार करना सबसे खतरनाक और आम उल्लंघनों में से एक है। समय बचाने के लिए कई लोग सीधे पटरियां पार करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर शराब के नशे में हंगामा करना, सार्वजनिक शांति भंग करना और अन्य यात्रियों को परेशान करना भी बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है।

महिला डिब्बों में बैठना भी जारी

कुछ मामलों में सीट पाने के लिए पुरुष यात्रियों द्वारा महिला डिब्बों में बैठने की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे महिला यात्रियों की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए आरपीएफ ने विशेष अभियान चलाए।

हॉकिंग और भीख मांगने के हजारों मामले

रेलवे परिसर में अवैध रूप से सामान बेचने, भीख मांगने और अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों के मामले भी बड़ी संख्या में सामने आए। वर्ष 2025 में ऐसे करीब 6,570 मामले दर्ज किए गए और लगभग उतने ही लोगों को पकड़ा गया। अधिकारियों के अनुसार रेलवे ट्रैक पार करने से रोकने के लिए कई स्थानों पर फुट ओवरब्रिज और अंडरपास भी बनाए गए हैं। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि पटरियां पार करना न केवल गैरकानूनी है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है।

ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी मामले में प्रोफेसर अली खान को राहत, हरियाणा सरकार ने बंद किया केस

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर पर की गई टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरे अशोका यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है।

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में आगे अभियोजन की अनुमति नहीं देगी और इसे एक बार की उदारता मानते हुए कार्रवाई बंद करने का फैसला किया है। सरकार के इस रुख के बाद यह मामला अब लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है। कोर्ट में बताया गया कि राज्य सरकार ने प्रोफेसर अली खान के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को बंद करने का फैसला किया है। सरकार ने इसे एक बार की उदारता (वन-टाइम मैग्नैनिमिटी) बताते हुए आपराधिक कार्रवाई को बंद करने का फैसला किया है। दरअसल, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर आरोप था कि उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर टिप्पणी की थी। बता दें कि 'ऑपरेशन सिंदूर' भारत की वह जवाबी कार्रवाई थी जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ की गई थी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच कर रही थी।

सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के पहले दिए गए सुझाव के बाद सरकार ने इस मामले को बंद करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि राज्य सरकार ने बताया है कि वह इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए अभियोजन की अनुमति नहीं देगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी है, लेकिन सरकार ने आगे केस न चलाने का फैसला लिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता एक पढ़े-लिखे और समझदार प्रोफेसर हैं और उम्मीद है कि वह आगे जिम्मेदारी से व्यवहार करेंगे। इस फैसले के बाद प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई अब खत्म होने की संभावना है।

शराब घोटाला केस - हाईकोर्ट ने केजरीवाल-सिसोदिया और बाकी को जवाब दाखिल करने का दिया समय, 6 अप्रैल को सुनवाई

नई दिल्ली ।

कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और इस मामले के अन्य आरोपियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित की गई है। नोटिस के बाद भी केजरीवाल या अन्य किसी आरोपी के द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह हर बार आरोप लगाकर भाग जाते हैं, न्यायिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि वह कुछ समय चाहते हैं क्योंकि इस मामले में बेंच बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है। जिसपर अदालत ने केजरीवाल की मांग पर जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया। बता दें कि कथित दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा कुल 23 आरोपियों को आरोपमुक्त किया था। कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में जज बदलने की मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पहले केजरीवाल ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मामले की सुनवाई किसी अन्य पीठ को सौंपने का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसी मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती दी है। सिसोदिया का कहना है कि हाईकोर्ट का समन कानूनन उचित नहीं है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

‘शिकार बनते शिकारी’

कहावत अमरीका और इसराईल पर जस की तस लागू होती है। हर दूसरे दिन जंग जीतने का दावा करने वाले जनाब डोनाल्ड ट्रम्प इन सवालों से कन्नी काट जाते हैं कि ‘जीत’ के बाद जंग क्यों जारी है? हालात गवाह हैं कि उनके पास न तो हमले का कोई वाजिब कारण था, न युद्ध से निकलने की कोई योजना। वह फंस गए हैं। 5000 साल पुरानी सभ्यताएं कुछ बमों से खत्म नहीं होतीं, यह ईरान ने साबित कर दिया है। आक्रमण के पहले ही दिन उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई अपने सर्वोच्च 44 साथियों के साथ मारे जाते हैं। इसराईल और अमरीका को लगा कि अब इराक की तरह बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर बगावत कर देंगे। हुआ इसका उलटा। लाखों लोग तेहरान में शोक मनाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। इसके साथ ही इसराईल और खाड़ी के देशों पर ईरानी ड्रोन अथवा मिसाइलें बरस उठती हैं। ऐसा इसलिए संभव हो सका, क्योंकि पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार, ‘सुप्रीम लीडर’ के गुजरते ही समूचे प्रशासनिक ढांचे को विकेंद्रीकृत कर दिया गया। अब हर क्षेत्रीय कमांडर परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सकता है। इससे झल्लाकर वाशिंगटन व तेल अवीव के हुक्मरानों ने और बड़े बमों की झड़ी लगा दी। यह सब इतने गैर-जिम्मेदाराना तरीके से किया गया कि 28 फरवरी को एक बालिका विद्यालय पर थोड़े अंतराल में 2 बार बमबारी की गई। नतीजतन, 168 बच्चियां और 14 अध्यापिकाएं शहीद हो गईं। नवनिर्वाचित ‘सुप्रीम लीडर’ अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई अमरीका और ट्रम्प को ‘दंडित’ कर ‘मुआवजा’ वसूलने का इरादा जाहिर कर रहे हैं। इससे पहले ईरान युद्धबंदी के लिए 3 शर्तें रख चुका है। आप इसे एक नौसिखिए का बड़बोलापन मानने को स्वतंत्र हैं, पर इतना तय है कि ईरान जैसा प्रतिरोध वाशिंगटन ने बरसों से नहीं देखा था। इससे अमरीकी चौधराहट की चमक धुंधली पड़ उठी है। पैट्रो डॉलर के बल पर अपनी और पश्चिम की झोलियां भरने वाले खाड़ी के हुक्मरानों ने अमरीकी सरपरस्ती में एक ऐसी दुनिया रची थी, जिसमें अमन-चैन और अमीरी थी। यह समझ खोखली साबित हो चुकी है। खाड़ी की घटती साख के साथ अमरीका और इसराईल को अन्य मोर्चों पर भी जबर्दस्त आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। सी.एन.एन. की रिपोर्ट के अनुसार, आक्रमण के शुरुआती 6 दिनों में ही 11 अरब अमरीकी डॉलर स्वाहा हो चुके थे। आजकल ईरानी हमलों से खाड़ी स्थित अमरीकी अड्डों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। अब तक वे संसार के समूचे मिसाइल भंडार का एक-तिहाई खर्च कर चुके हैं। इसकी बरसों तक भरपाई नहीं की जा सकेगी, क्योंकि इनकी निर्माण क्षमता भी सीमित है। उधर, प्रतिस्पर्धी चीन का धन और बल, दोनों सुरक्षित हैं। हालात इतने संगीन हैं कि अमरीका को दक्षिण कोरिया, जापान आदि देशों में तैनात मिसाइल खाड़ी स्थित अड्डों पर मंगवाने पड़े हैं। इससे सवाल उठने लगे हैं, दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरिया या जापान पर चीन हमलावर हो उठे, तो अमरीकी उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे? इससे कुछ नए सामरिक समीकरण उभर सकते हैं। अमरीका के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। इस युद्ध ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष से उभरे एक तथ्य को स्थापित कर दिया है। वह यह कि अब लड़ाई सिर्फ भारी-भरकम हथियारों और सैनिक दस्तों से नहीं जीती जा सकती। उसे रोकने के लिए छोटे से छोटा देश ड्रोन और नई टैक्नोलॉजी का सहारा लेकर खुद को लंबे समय तक बचाए रख सकता है। महज 20000 डॉलर वाले ईरानी शाहिद ड्रोन को नाकाम करने के लिए पेंटागन को 40 लाख डॉलर की मिसाइल खर्च करनी पड़ती है। यह युद्ध अगर लंबा इक्षखच गया, तो इसराईल बदहाल और अमरीका मंदी का शिकार बन सकता है। उनको कूटनीति के मोर्चे पर भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। स्पेन ने तेल अवीव में अपना दूतावास बंद कर दिया है। आगे कुछ और देश ऐसा कर सकते हैं। अमरीका के इटली जैसे सहयोगी ने पहले ही कह दिया है कि वह युद्ध में शामिल नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प और बेंजामिन नेतन्याहू के इस अविवेकी निर्णय ने विश्व की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। कच्चे तेल की कीमतें शनिवार की दोपहर तक 102 डॉलर प्रति बैरल के करीब जा पहुंची थीं। समूची दुनिया के शेयर बाजार कंपकंपा रहे हैं और कई देशों में ऊर्जा की आपूर्ति चरमराने लगी है। खुद अमरीका में ही ट्रम्प का विरोध जोर पकड़ता जा रहा है। यहां 70 फीसदी से ज्यादा लोग इस अकारण के आक्रमण से नाखुश हैं। जल्द होने वाले उपचुनावों में ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी को आघात का सामना करना पड़ सकता है, वहीं समूची दुनिया में अमरीका विरोध की भावनाएं जोर मार सकती हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे अमरीकी साम्राज्य के पराभव की शुरुआत बता रहे हैं। 9/11 के बाद से अमरीका लगातार नुकसानदेह लड़ाइयों में फंसता रहा है। उसकी फौजें ईराक को बदहाल छोड़ने के बाद अफगानिस्तान से भी परेशान होकर लौटी थीं। उन्हें सीरिया, सोमालिया और लीबिया से भी उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं हासिल हुए। यही नहीं, हर अमरीकी जंग चीन के लिए तोहफा साबित होती है। बीजिंग ने 1979 के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा और कारोबार पर ध्यान दिया। आज उसे ‘दुनिया का कारखाना’ कहा जाता है। अब अपने देश की बात करते हैं। हमारा लगभग 50 फीसदी तेल और 90 प्रतिशत एल.पी.जी. गैस होर्मुज की खाड़ी से गुजरती है। ईरान ने चीन के अलावा सभी के लिए इसे बंद कर दिया था, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री के विशेष प्रयासों से भारतीय पोतों को कुछ छूट दी गई है। अगर खाड़ी कुछ और दिन बंद रही, तो हमारे सामने नई चुनौतियां आ खड़ी होंगी। सरकार ने इसीलिए एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। गैस के व्यावसायिक उपयोग पर रोक के साथ घरेलू गैस की बुकिंग भी अब निश्चित समय बीतने के बाद ही कराई जा सकेगी। इससे अभी से कई स्थानों पर अफरातफरी मच गई है। गैस एजेंसियों पर कतारें लगी हैं, बिजली के चूल्हे बाजार से नदारद हो गए हैं, ढाबों और छोटे रेस्तरांओं में मैन्यू को सीमित कर दिया गया है।

सम्पादकीय...

पढ़ाई की योजनाएं

कंसल्टैंट्स का कहना है कि अमरीका में सख्त वीजा नीतियां, खासकर डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में और ब्रिटेन, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन के कड़े नियम और पढ़ाई के बाद काम करने के कम होते मौकों के साथ-साथ पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष, कई भारतीय छात्रों को अपनी विदेश में पढ़ाई की योजनाओं को रोकने या उनमें बदलाव करने पर मजबूर कर रहे हैं। हाल के महीनों में, कई छात्रों ने विदेशी यूनिवर्सिटीज में दाखिले के अपने प्लान को अगले सैशन तक के लिए टाल दिया है, जबकि वैश्विक अशांति और अनिश्चितता के बीच कुछ छात्र अपने घर के करीब या ज्यादा स्थिर जगहों पर पढ़ाई के विकल्प तलाश रहे हैं। कॉलेजीफाई के सह-संस्थापक और निदेशक आदर्श खंडेलवाल ने कहा, ‘‘विदेश में पढ़ाई के रुझानों में एक साफ गिरावट देखी जा रही है। सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीयों की संख्या 2023 में 9,08,000 से घटकर 2025 में 6,26,000 रह गई है, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट है।’’ उन्होंने आगे कहा कि भारत को अब सिर्फ एक ‘बैकअप’ (दूसरा विकल्प) के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे तेजी से एक गंभीर ‘पहली पसंद’ वाले माहौल के तौर पर परखा जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, माता-पिता अपने बच्चों को विदेश भेजने से पहले ज्यादा सोच-समझकर फैसले ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों के बीच सबसे बड़ी चिंता ‘नीतियों में अनिश्चितता’ है, न कि युद्ध। आई.डी.पी. एजुकेशन के क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण एशिया, कनाडा और लाटाम) पीयूष कुमार ने कहा, ‘‘विदेशों में पढ़ाई के मुख्य ठिकानों से मिले हालिया सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले छात्रों की विदेश यात्रा की रफ्तार धीमी हो गई है।’’ उदाहरण के लिए, अमरीकी विदेश विभाग के आंकड़े दिखाते हैं कि जून और जुलाई 2025 के बीच विदेशी छात्रों को जारी किए गए वीजा की संख्या में 62 प्रतिशत की गिरावट आई है। कुमार के अनुसार, ‘‘इस गिरावट के पीछे कई वजहें हैं, जिनमें सख्त वीजा नीतियां, नए ग्रैजुएट्स के लिए मुश्किल जॉब मार्केट और करंसी में उतार-चढ़ाव शामिल हैं।’’ पोस्ट ग्रैजुएट (स्नातकोत्तर) स्तर पर इसका असर ज्यादा पड़ा है। कुमार ने आगे कहा, ‘‘कई इच्छुक छात्र ऐसे कामकाजी पेशेवर हैं, जो अपनी पढ़ाई की योजनाओं को 1 या 2 साल के लिए टालना पसंद कर रहे हैं।’’ वे मौजूदा उथल-पुथल के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। विकल्पों को फिर से तय करना = कंसल्टैंट्स के अनुसार, इस क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति के कारण यू.ए.ई. जाने वाले आवेदनों में भी अस्थायी गिरावट आई है। लैवरेज एजुकेशन के संस्थापक और सी.ई.ओ. अक्षय चतुर्वेदी ने कहा, ‘‘बड़े स्तर पर, 2026 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की मांग किसी संरचनात्मक गिरावट की बजाय, गंतव्य विकल्पों में फिर से बदलाव और विविधता लाने के दौर को दर्शाती है।’’ कॉलेजीफाई के खंडेलवाल ने कहा, ‘‘जब कोई संघर्ष होता है, अस्थिरता को लेकर मीडिया में लगातार खबरें आती हैं, तो इससे घरों का भावनात्मक माहौल बदल जाता है।

तीसरी दुनिया की संप्रभुता पर साम्राज्यवाद का हमला

प्रभात पटनायक

अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सभी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, साम्राज्यवाद अब तीसरी दुनिया के देशों की संप्रभुता की अवधारणा को ही ध्वस्त करना चाहता है। शासन परिवर्तन (रिजीम चेंज) के घोषित और स्पष्ट लक्ष्य के साथ, ईरान पर अमेरिका तथा इस्राइल के हमले से यह स्पष्ट है। अब तक, जब साम्राज्यवाद के मनमाफिक न पड़ने वाले किसी निजाम को बदलने के स्वतः स्पष्ट उद्देश्य को लेकर वे कार्रवाई करते थे, तब भी साम्राज्यवादी सैन्य हस्तक्षेप के लिए आधिकारिक रूप से जो कारण बताया जाता था, उसमें किसी और बहाने को पर्दे की ओट बनाने की कोशिश की जाती थी। मिसाल के तौर पर इस तरह के बहाने बनाए जाते थे कि संबंधित निजाम के पास ‘‘जन-संहार के शस्त्र’’ थे या संबंधित निजाम मादक द्रव्यों के व्यापार में संलिप्त था या ऐसा ही कोई और बहाना। लेकिन, ईरान के मामले में उस तिनके की ओट को भी छोड़ दिया गया है। ईरान के खिलाफ बमबारी तब शुरू कर दी गयी, जब ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम पर, जो कि प्रकटत विवाद का मुद्दा था, वार्ताएं चल ही रही थीं और जैसा कि बताया जाता है, उनमें प्रगति भी हो रही थी। इस तरह, औपनिवेशिक दौर के खत्म होने के बाद पहली बार, इस कार्रवाई के जरिए अमेरिका ने यह अधिकार हथिया लिया है कि तीसरी दुनिया में वह जब भी चाहे, शासन परिवर्तन या रिजीम चेंज करा सकता है। यहां नुक्ता यह नहीं है कि ईरान के इस्लामी गणराज्य को, ईरानी जनता के बीच जन-समर्थन हासिल है या नहीं या यह निजाम दमनकारी है या नहीं या वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है या नहीं या यह निजाम विपक्ष को बर्दाश्त करता है या नहीं। नुक्ता यह है कि सिर्फ और सिर्फ ईरान की जनता को यह तय करने का अधिकार है कि उनके देश में कौन सा निजाम होना चाहिए या क्या वर्तमान निजाम को बदला जाना चाहिए और देश की जनता को ही इस बदलाव के लिए काम करने का अधिकार है। यह तय करना साम्राज्यवाद का काम नहीं है और उसे वैसे भी किसी दूसरे देश के मामलों में सैन्य हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी देश की संप्रभुता इसी को कहते हैं और दूसरे विश्व युद्ध के बाद समूची तीसरी दुनिया में अपने-अपने देश में, उपनिवेशविरोधी संघर्षों के जरिए यही संप्रभुता हासिल की गयी थी। लेकिन, जो साम्राज्यवाद अब तक भांति-भांति की पिछले दरवाजे की तिकड़मों के जरिए इस संप्रभुता को कमजोर करने में लगा रहा था, उसने अब ऐसा करने के लिए खुल्लमखुल्ला सैन्य हस्तक्षेप का सहारा लेना शुरू कर दिया है। यह सीधे-सीधे राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला है और इसलिए यह इतिहास के एक नये ही अध्याय की शुरूआत का सूचक है। यह व्यावहारिक मानों में निरुपनिवेशीकरण के पलटे जाने का रास्ता तैयार करता है।

साम्राज्य की हिम्मत, साम्राज्यवाद का संकट

इससे सीधे-सीधे दो सवाल उठते हैं। एक तो यह कि साम्राज्यवाद की ऐसा हमला करने की हिम्मत कैसे पड़ रही है? दूसरे, उसे खासतौर पर इस मुकाम पर ऐसा करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? पहले सवाल का जवाब आसान है। सोवियत संघ के पराभव और शीत युद्ध के अंत ने उसे ऐसी हैसियत में ला दिया है, जहां उसे पहले की तरह अपने हाथ बंधे हुए महसूस नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर क्यूबा के मामले में, जहां के लिए भी साम्राज्यवाद शासन परिवर्तन की बात कर रहा है, आज की स्थिति की तुलना अगर 1962 के क्यूबाई मिसाइल संकट के समय से करते हैं, तो अंतर हैरान कर देता है। उस समय सोवियत संघ ने क्यूबा की ओर बढ़ रहे अपने पोतों को आदेश दे दिया था कि इस द्वीप की अमरीकी नाकेबंदी को बलपूर्वक तोड़ते हुए निकल जाएं और इस तरह उसने इससे नाभिकीय युद्ध छिड़ने तक का खतरा उठाया था। तब अमेरिका को ऐसी नौबत आने से बचने के लिए समझौता करना पड़ा था। इसका एक नतीजा यह हुआ कि उसके बाद से, क्यूबा के खिलाफ किसी प्रत्यक्ष साम्राज्यवादी हस्तक्षेप की नौबत नहीं आयी थी। लेकिन, साम्राज्यवाद पर उस तरह का अंकुश अब नहीं रहा है। बेशक, इस तरह का अंकुश तो पिछले काफी समय से नहीं है, लेकिन जैसी कि मैं आगे चर्चा करूंगा, साम्राज्यवाद इस समय अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है और यही उसे तीसरी दुनिया का दोबारा उपनिवेशीकरण करने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। पीछे हमने जो दूसरा सवाल रखा था, उसका यही जवाब है। साम्राज्यवाद के वर्तमान संकट की प्रकृति को हम सही ढंग से तभी समझ सकते हैं, जब हम यह ध्यान में रखें कि इसके दो अलग-अलग घटक हैं। पहला यह कि पिछले तीन-चार दशक के दौरान विकसित देशों में राष्ट्रीय आय में मजदूरों के हिस्से और तीसरी दुनिया के देशों में राष्ट्रीय आय में मेहनतकशों के हिस्से में भारी गिरावट हुई है। और चूंकि इकाई आर्थिक अधिशेष में से उपभोग का हिस्सा, मजदूरों या मेहनतकशों की इकाई आय में से इसी हिस्से से कम होता है, यह सकल मांग के सापेक्ष अधि-उत्पादन या ओवर प्रोडक्शन की प्रवृत्ति पैदा करता है और इसलिए बेरोजगारी में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति पैदा करता है। यह दूसरी बात है कि बेरोजगारी में इस बढ़ोतरी को आवरणों के पीछे छुपाया जा सकता है, जैसे अमेरिका में इसे श्रम भागीदारी की दर में गिरावट की ओट में छिपाया जा रहा है। इसका अर्थ है, मेहनतकश जनता की बदहाली में भारी बढ़ोतरी।

अमेरिका का व्यापार घाटा- साम्राज्यवाद की कमज़ोरी

साम्राज्यवाद के वर्तमान संकट में योग दे रहा दूसरा कारक यह है कि वह जब अपने शिखर पर था तब के यानी पहले विश्व युद्ध से पहले के दौर के विपरीत, आज की साम्राज्यवाद की नेतृत्वकारी शक्ति के पास इसकी सामर्थ्य ही नहीं है कि एक औपनिवेशिक साम्राज्य पर अधिशेष की निकासी या ड्रेन ऑफ सरप्लस या निरुद्योगीकरण थोपने के जरिए, अपने भुगतान संतुलन घाटे की भरपाई कर सके। याद रहे कि नेतृत्वकारी साम्राज्यवादी देश को अपरिहार्य रूप से भुगतान संतुलन घाटा उठाना पड़ता है। और वर्तमान मामले में अमेरिका के घाटे का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि वह अपने वैश्विक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए, दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में, 750 से ज्यादा सैनिक अड्डों की शृंखला को चला रहा है। पहले विश्व युद्ध से पहले के दौर में, तब की नेतृत्वकारी साम्राज्यवादी ताकत, ब्रिटेन द्वारा इस भुगतान संतुलन घाटे की भरपाई, अपने उपनिवेशों की कीमत पर की जाती थी। लेकिन, चूंकि आज की नेतृत्वकारी साम्राज्यवादी ताकत, अमेरिका के पास उस तरह अपना कोई औपनिवेशिक साम्राज्य है ही नहीं, इसका नतीजा यह हुआ है कि वह डॉलर छाप-छाप कर अपने भुगतान संतुलन घाटे की भरपाई करता रहा है। इसका नतीजा यह है कि अमेरिका आज दुनिया का अब तक का सबसे ज्यादा कर्जदार देश बन गया है और दुनिया डालरों से या अमेरिका की देनदारी की सूचक, डॉलर मूल्यांकित परिसंपत्तियों से पटी पड़ी है। इससे, पूंजीवादी विश्व वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता के लिए भारी खतरा पैदा हो गया है। अक्सर यह इशारा किया जाता है कि जितना प्रयोग डालर का होता है, उतना और किसी भी मुद्रा का नहीं होता है और डालर के सामने कोई वास्तविक चुनौती ही नहीं है। लेकिन, यह धारणा भ्रामक है। भले ही डालर को किसी दूसरी मुद्रा से चुनौती नहीं मिल रही हो, अचानक डालर को छोड़कर, मालों के रूप में संपदा रखे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है और ऐसा भले ही कुछ ही समय के लिए हो तब भी, इससे पूंजीवादी दुनिया में भारी मंदी पैदा हो सकती है। 1970 के दशक के आरंभ में ठीक ऐसा ही हुआ था और यही वह पृष्ठभूमि थी जिसमें थैचरवाद तथा रीगनी अर्थशास्त्र या रीगनोमिक्स का उदय हुआ था, जिन्होंने मुद्रास्फीति की काट करने के लिए अपने-अपने देशों में भारी बेरोजगारी पैदा की थी। लेकिन, तब मजदूरों पर यह बोझ ऐसे हालात में थोपा जा रहा था, जब उससे पहले मजदूरों ने एक उल्लेखनीय युद्धोत्तर उछाल देखा था। लेकिन, वर्तमान हालात में वैसी स्थितियों का कोई भी दोहराव, चूंकि मजदूरों की भारी बदहाली के ऊपर से आ रहा होगा, जिसके कारणों का हम पीछे जिक्र कर आए हैं, इससे पूंजीवादी व्यवस्था की सामाजिक स्थिरता ही बुरी तरह से उलट-पुलट हो सकती है।

इस परिस्थिति संयोग में, इस तरह के खतरे को रोकने के लिए, साम्राज्यवाद के प्रत्युत्तर के दो घटक हैं। पहला, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के रूप में (और अन्यत्र ऐसे ही निजाम या ऐसे ही बन सकने वाले निजामों के रूप में) नव-फासीवादी निजामों का कायम किया जाना। दूसरा है, अपने आज्ञापालक निजाम कायम करने के जरिए, दुनिया भर में औपनिवेशिक शैली का प्रभुत्व कायम करने की कोशिश करना। वेनेजुएला के निकोलस मादुरो का आपराधिक अपहरण और ईरान पर हमला, जहां पहलवी वंश की औलाद, अमेरिका की कृपा से सत्ता संभालने के लिए तैयार बैठी है, इसी तरह के पुनरुपनिवेशीकरण के उदाहरण हैं। वेनेजुएला और ईरान, दोनों तेल धनी देश हैं और वेनेजुएला में तो तेल के दुनिया के सबसे बड़े संचित भंडार हैं। उनके तेल भंडारों पर अमरीकी कंपनियों का कब्जा, अधिशेष के बहिप्रवाह या ड्रेन ऑफ सरप्लस के एक और चक्र का रास्ता खोलेगा। इस बार यह प्रवाह अमेरिका की ओर हो रहा होगा, जो अमेरिका की भुगतान संतुलन की समस्याओं को कम करने का काम करेगा। बहरहाल, यह पुनरुपनिवेशीकरण सिर्फ तेल धनी देशों से इस तरह की लूट या ड्रेन तक ही सीमित नहीं है। यह भारत-अमेरिका व्यापार संधि जैसी असमानतापूर्ण संधियां थोपने की कोशिश का भी रूप लेता है, जो संधियां अमरीकी मालों के लिए बंधुआ बाजार जुटाएंगी, जैसा कि औपनिवेशिक दौर में हुआ करता था। बेशक, यह तो एक अलग ही सवाल है कि क्या साम्राज्यवाद पुनरु पनिवेशीकरण की इस तरह की कोशिशों से अपने वर्तमान संकट से उबरने में कामयाब हो जाएगा?

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कन्हा ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/08862)

जनगणना का कार्य त्रुटिरहित व पारदर्शी ढंग से करें- मंडलायुक्त अनिल ढींगरा

कुशीनगर।

अनिल ढींगरा, मंडलायुक्त गोरखपुर मंडल ने सोमवार को जनपद कुशीनगर के भ्रमण के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार कुशीनगर में आयोजित जनगणना से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाती है।

उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से जनगणना के उद्देश्य और महत्व को भली-भांति समझने तथा किसी भी प्रकार की दुविधा होने पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी। उन्होंने निर्देश दिया कि जनगणना का कार्य पूरी सावधानी और त्रुटिरहित ढंग से किया जाए तथा किसी भी परिवार की जानकारी अधूरी न रहे। साथ ही जनगणना से जुड़ी सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने पर भी बल दिया। मंडलायुक्त ने बताया कि जनगणना का कार्य दो चरणों में संपन्न होगा।

पहले चरण में मकानों का सूचीकरण एवं गणना 22 मई से 20 जून 2026 तक की जाएगी। इसके पूर्व 7 मई से 21 मई 2026 तक नागरिकों को स्व-गणना पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार से संबंधित विवरण स्वयं दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी। दूसरे चरण में जनसंख्या गणना का कार्य 28 फरवरी 2027 तक पूरा कराया जाएगा। इसके बाद मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी कार्यालय

में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के साथ बैठक कर राजस्व वादों की समीक्षा की। उन्होंने धारा-24, धारा-34, धारा-80 सहित अन्य मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि पुराने राजस्व वादों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और इस माह के अंत तक अधिकतम मामलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उपजिलाधिकारियों को न्यायालय की कार्यवाही की नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए। मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि मैपिंग के बाद जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं उनसे फार्म भरवाकर लंबित मामलों को समाप्त किया जाए। उन्होंने ऐसे बूथों को चिन्हित करने और संबंधित बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जहाँ 10 से कम फार्म भरे गए हैं।

साथ ही 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के नए मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने पर विशेष ध्यान देने को कहा। भ्रमण के दौरान मंडलायुक्त ने कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न पटलों का निरीक्षण भी किया। शिकायत प्रकोष्ठ का निरीक्षण करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि आईजीआरएस पर कोई भी शिकायत लंबित न रहे तथा सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री संदर्भित शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निस्तारित करने और किसी भी प्रकरण को डिफॉल्टर श्रेणी में न जाने देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान भूमि सुधार, लोकवाणी, संयुक्त कार्यालय, नजारत और जिला पूर्ति कार्यालय सहित अन्य पटलों का भी अवलोकन कर अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव और इंडेक्स तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कोरोना के बाद पत्रकारिता के सामने विश्वसनीयता का संकट - रणविजय सिंह

कप्तानगंज,कुशीनगर ।

गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के 42वें शपथ ग्रहण समारोह में पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और चुनौतियों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार एवं पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रणविजय सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद पत्रकारिता के सामने सबसे बड़ा संकट विश्वसनीयता का खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले पत्रकार समाचार के साथ उसका विश्लेषण भी प्रस्तुत करता था, जबकि आज एआई सूचना तो देता है, लेकिन उसमें विश्वसनीयता और मानवीय विश्लेषण का अभाव होता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद मीडिया संस्थानों के बंद होने और रोजगार के अवसर घटने से पत्रकारिता को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए पत्रकारों को समय के साथ खुद में बदलाव लाना होगा। समारोह में एसोसिएशन के पत्रकारों को शपथ दिलाई गई और विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान स्व. फूल नारायण धर द्विवेदी को मरणोपरांत लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, रविंद्र शर्मा को 42 वर्ष की सेवा के लिए स्व. यती वर्मा स्मृति विलक्षण प्रतिभा सम्मान, मुकीम सिद्दीकी को लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. ढिल्लों स्मृति सम्मान तथा वरिष्ठ हाकर पारसनाथ गुप्ता को स्व. डी.के. गुप्ता स्मृति प्रतिभा सम्मान प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि हेमंत तिवारी ने कहा कि समाज पत्रकार से सच्चाई और सटीक जानकारी की अपेक्षा करता है, लेकिन पत्रकारों की समस्याओं को समझने वाला कम है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अनेक पत्रकारों ने अपनी जान गंवाई और कई मीडिया संस्थान बंद हो गए, इसलिए अब पत्रकारों को नई तकनीक के साथ तालमेल बैठाना होगा। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. रामकृपाल राय, सीपीआरओ पूर्वोत्तर रेलवे पंकज सिंह, समूह संपादक अनाम पांडे तथा अखिलेश चंद्र ने भी पत्रकारिता की चुनौतियों और बदलते दौर पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन मृत्युंजय उपाध्याय नवल ने किया। अंत में सिंदूर ऑपरेशन में शहीद सैनिकों तथा पिछले एक वर्ष में दिवंगत पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी गई और राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। समारोह में गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया शाखा के लगभग 200 पत्रकारों सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

खड्डा में सर्वजन-हित पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन, मिशन 2027 को लेकर भरी हुंकार

खड्डा,कुशीनगर।

अखिल भारतीय सर्वजन-हित पार्टी की विधानसभा क्षेत्र 329 खड्डा का कार्यकर्ता सम्मेलन स्थानीय राजश्री पैलेस में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के संयोजक व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता विजय कुमार पाण्डेय के आह्वान पर बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता सम्मेलन में जुटे। इस दौरान कई युवाओं और समर्थकों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर संगठन को मजबूत करने और मिशन 2027 के लिए काम करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण चौबे ने यूजीसी बिल वापस लेने की मांग दोहराते हुए रसोई गैस की किल्लत और केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियों से किसान और देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक पाण्डेय ने महंगाई, बेरोजगारी और प्रशासनिक व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि किसानों को अपने उत्पाद बेचने में भी बिचौलियों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कार्यक्रम के संयोजक विजय कुमार पाण्डेय ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को वीरेंद्र मिश्र बिरही, श्रीराम तिवारी, सोनू मणि त्रिपाठी, अशोक पाण्डेय, डॉ. वृजविहारी पाण्डेय, विजय पाठक, विजय पाण्डेय द्वितीय, संगीता भारती, अनदिनाथ, राजू पाठक, कलमुल्ला अंसारी सहित कई नेताओं ने भी संबोधित किया।

कुशीनगर के लिए बड़ी खुशखबरी- अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से नियमित उड़ानों का रास्ता साफ, जल्द जारी होगी समयसारिणी

कुशीनगर। जनपद कुशीनगर और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक बड़ी और बहुप्रतीक्षित खुशखबरी सामने आई है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से नियमित विमान सेवाएं शुरू होने का मार्ग अब लगभग प्रशस्त हो गया है। उड़ान संचालन से जुड़ी सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और शीघ्र ही विमान सेवाओं की समयसारिणी (शेड्यूल) घोषित किए जाने की संभावना है।

बताया गया है कि इस संबंध में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू से मुलाकात कर कुशीनगर एयरपोर्ट से नियमित उड़ानों के संचालन पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने से जुड़े तकनीकी पहलुओं, प्रशासनिक प्रक्रियाओं तथा जन-आकांक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि कुशीनगर से हवाई सेवाओं के संचालन में आने वाली तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं को दूर कर लिया गया है तथा अब नियमित उड़ानों की शुरुआत का रास्ता साफ हो चुका है। जल्द ही विमान सेवाओं का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिलने लगेगी। गौरतलब है कि कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध तीर्थस्थल के रूप में विख्यात है और यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं। एयरपोर्ट से नियमित उड़ान सेवा शुरू होने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि व्यापार, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए केंद्रीय मंत्री के. राममोहन नायडू के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जन-आकांक्षाओं को प्राथमिकता देते हुए तकनीकी समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे कुशीनगर सहित पूर्वांचल के लोगों को देश के प्रमुख शहरों से सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा, पदाधिकारियों ने दी बधाई

कुशीनगर । भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर सोमवार को भाजपा कार्यालय रविन्द्र नगर में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई देते हुए उनके अब तक के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष को बुके भेंट कर संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाए रखने तथा जनसेवा के प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय के नेतृत्व में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य किया गया है और पार्टी

की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। पदाधिकारियों ने उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आगामी समय में भी उनके मार्गदर्शन में संगठन और अधिक सशक्त होगा। उन्होंने जिलाध्यक्ष के दो वर्षीय कार्यकाल को जनसेवा और संगठन के लिए समर्पित बताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पार्टी के सभी पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों और समर्पित कार्यकर्ताओं की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की बदौलत कुशीनगर में संगठन और सरकार दोनों लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे भी संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला महामंत्री सुदर्शन पाल, जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल, जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनन्द, प्रवीण गुंजन, मंडल अध्यक्ष रामप्रवेश कसौधन, अवधेश सिंह, राजेश सिंह, संदीप श्रीवास्तव, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल प्रताप राव, दिव्यांग प्रकोष्ठ जिला सह संयोजक धन्नजय मणि त्रिपाठी, मनीष विश्वकर्मा, अरुण राय, विकास जायसवाल, मनीष चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

एलपीजी की कमी से दिल्ली में हाहाकार! अटल कैंटीन, रैन बसेरों में खाने का संकट, कांग्रेस का का सरकार पर हमला

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कथित कमी को लेकर सियासत तेज हो गई है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि गैस सिलेंडर की कमी के कारण गरीबों के लिए चल रही सरकारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. उनका कहना है कि दिल्ली की अटल कैंटीन और रैन बसेरों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार हालात सामान्य होने का दावा कर रही है. देवेंद्र यादव ने कहा कि एलपीजी सिलेंडर की कमी से अब सरकार की योजनाएं भी प्रभावित होने लगी हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की अटल कैंटीन और रैन बसेरों में रहने वाले गरीब आश्रितों को खाना मिलना लगभग बंद होने की स्थिति में है. उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों जनता को यह कहकर दिलासा दे रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है.

उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार की गलत नीतियों और नाकामी के कारण गरीब और जरूरतमंद लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं. इसके चलते अटल कैंटीन जैसी योजनाओं में संकट खड़ा हो गया है. पांच रुपये में मिलने वाली थाली के लिए अब लोगों की भीड़ चार गुना तक बढ़ चुकी है. दिल्ली में चल रही 71 अटल कैंटीन सिलेंडर की कमी के कारण सुबह और शाम मिलाकर एक दिन में करीब 1000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में भी विफल साबित हो रही हैं।

रैन बसेरों में भी खाने का संकट गहराया

देवेंद्र यादव ने कहा कि यही स्थिति दिल्ली सरकार के रैन बसेरों में भी देखने को मिल रही है. गैस सिलेंडर की आपूर्ति ठप होने के कारण वहां रहने वाले आधे से अधिक लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने बताया कि राजधानी के अधिकतर रैन बसेरों में पिछले लगभग दो सप्ताह से केवल 40 प्रतिशत लोगों को ही खाना दिया जा रहा है. कई लोगों को रात में भूखे ही सोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

कई इलाकों की अटल कैंटीन प्रभावित

उन्होंने कहा कि नरेला, मंगोलपुरी, सैदपुर, बुध विहार, इंद्रपुरी, गीता कॉलोनी, शिलमिल और आर.के. पुरम समेत कई इलाकों की अटल कैंटीन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने में असफल हो रही है. अटल कैंटीन संचालित करने वाले लोग भी सिलेंडर न मिलने के कारण खुद को असहाय बता रहे हैं. हालात यह है कि घरों में गैस सिलेंडर नहीं होने के कारण लोग भूख से परेशान होकर अटल कैंटीन के बाहर तीन से चार घंटे पहले ही टोकन लेने के लिए लाइन में लग रहे है.

ओडिशा-कटक के सरकारी हॉस्पिटल में आग लगने से 10 मरीजों की मौत

11 कर्मचारी भी झुलसे; मृतकों के परिजन को 25-25 लाख मुआवजा

नई दिल्ली । ओडिशा के कटक में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस घटना की जानकारी दी है। हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री तुरंत अस्पताल पहुंचे और मौके पर हालात का जायजा लिया। इस घटना पर देश के तमाम बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है

राष्ट्रपति ने जताया दुख

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को ओडिशा के अस्पताल में आग लगने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया।

उन्होंने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। घटना पर राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने लिखा, ओडिशा के कटक में एक अस्पताल में आग लगने की दुखद घटना में लोगों की मौत से मुझे बहुत दुख हुआ है। शोक में डूबे परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करती हूं।

अस्पताल हादसे पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख

वहीं ओडिशा के कटक में हुए अस्पताल हादसे पर प्रधानमंत्री ने भी गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ओडिशा के कटक स्थित एक अस्पताल में हुई दुर्घटना अत्यंत दुखद है। अपनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा कोष (पीएमएनआरएफ) से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

जंग के बीच एलपीजी लेकर भारत पहुंचा शिवालिक जहाज

तेल अवीव/तेहरान ।

अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 17वां दिन है। इस बीच भारतीय जहाज शिवालिक कतर से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेकर भारत गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा । जहाज लगभग 46 हजार मीट्रिक टन एलपीजी लेकर पहुंचा। एक घरेलू सिलेंडर में लगभग 14.2 किलोग्राम एलपीजी भरी जाती है। इस प्रकार 46 हजार मीट्रिक टन में 32.4 लाख घरेलू सिलेंडर भरे जा सकते हैं। 14 मार्च को ईरान ने शिवालिक को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दी थी।

वहीं, जहाज नंदा देवी और जग लाडकी कल तक भारत पहुंच सकता है। नंदा देवी जहाज पर भी 46,000 टन एलपीजी लदा है।

ईरान ने इजराइल पर 'सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल' दागी

ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि इजराइल के सैन्य और डिफेंस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। यह सॉलिड फ्यूल वाली स्ट्रैटेजिक मिसाइल है, जो 2000-2500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। द नेशनल इंटरेस्ट पत्रिका के अनुसार, इस मिसाइल की पहुंच मिस्र, सूडान के कुछ हिस्सों, यूक्रेन के बड़े हिस्से, दक्षिणी रूस, पश्चिमी चीन, भारत और हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बड़े क्षेत्रों तक हो सकती है।

ग्रोक ने नेतन्याहू के वीडियो को 'डीपफेक' बताया

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक कॉफी पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। कुछ लोग इसे एआई से बना 'डीपफेक' बता रहे हैं। वीडियो में नेतन्याहू एक कैफे में कॉफी ऑर्डर करते नजर आते हैं। यह वीडियो उस वक्त सामने आया जब सोशल मीडिया पर उनके मरने की अफवाहें फैल रही थीं। एक्स के एआई चैटबॉट ग्रोक ने भी एक यूजर के सवाल पर इसे एआई से बना वीडियो बताया। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि नेतन्याहू पूरी तरह ठीक हैं और उनकी मौत की खबरें फेक हैं।

आज नंदा देवी-जग लाडकी शिप भी पहुंचेंगे

बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सिलीगुड़ी-हावड़ा समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी की टीमों ने राज्य के अलग-अलग कई इलाकों में छापेमारी की। यह पूरी कार्रवाई एक अवैध कॉल सेंटर चलाने और लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले से जुड़ी है। अधिकारियों ने बताया कि सिलीगुड़ी, हावड़ा, बिधाननगर और दुर्गापुर जैसे इलाकों में करीब 10 जगहों पर तलाशी ली गई। इस मामले में सुरक्षी कर, समाट घोष और सुभजीत चक्रवर्ती के नाम मुख्य रूप से सामने आए हैं। एजेंसी इन लोगों और इनके साथियों के ठिकानों पर जरूरी सबूत तलाश रही है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने कॉल सेंटर के जरिए बहुत से मासूम लोगों को अपना शिकार बनाया और उनसे बड़ी रकम ठगी है। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि इस मामले का कोई संबंध चुनावी फंडिंग या राजनीति से है या नहीं। जांच एजेंसी हर पहलू से मामले की पड़ताल कर रही है।

भाजपा की सुविधानुसार तय होती हैं चुनाव की तारीखें - प्रियंका गांधी

नई दिल्ली । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के बाद सोमवार को दावा किया कि भाजपा की सहूलियत के हिसाब से चुनाव की तारीखें और चरण तय किए जाते हैं। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, जिस तरह से चुनावों की तारीखों की घोषणा होती है और चरणों को निर्धारित किया जाता है, उससे मुझे लगता है कि ये सब भाजपा की सुविधानुसार तय होता है। निर्वाचन आयोग ने रविवार को पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। सभी राज्यों में मतगणना चार मई को होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दो चरण में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा। केरल, असम और पुडुचेरी के लिए नौ अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा।

एलपीजी किल्लत पर राज्यसभा में भिड़े खरगे- नड्डा

नई दिल्ली ।

सोमवार को राज्यसभा में रसोई गैस की किल्लत और इसके चलते देशभर में मचे हाहाकार का मुद्दा गरमाया रहा।

विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में शून्यकाल के दौरान देश में व्याप्त गैस संकट पर गहरी चिंता जताई, जिस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया।

खरगे बोले- 5000 रुपए में मिल रहा है सिलेंडर

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने देश की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि गरीब, मध्यम वर्ग, हॉस्टल और छोटे दुकानदार इस किल्लत से बुरी तरह प्रभावित हैं। सामुदायिक रसोई और चैरिटेबल सेंटर तक बंद होने की कगार पर हैं। इसी के साथ उन्होंने याद दिलाया कि

भारत अपनी जरूरत का 60फीसदी एलपीजी आयात करता है, जिसका 90फीसदी हिस्सा रणनीतिक रूप से संवेदनशील स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर आता है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि कुछ जगहों पर व्यावसायिक गैस सिलेंडर 5,000 रुपये से अधिक की कीमत पर बिक रहे हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि पहले से वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए गए?

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने देश की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि गरीब, मध्यम वर्ग, हॉस्टल और छोटे दुकानदार इस किल्लत से बुरी तरह प्रभावित हैं।

पलटवार करते हुए जेपी नड्डा बोले

सदन में खड़गे के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है और विपक्ष को इस संवेदनशील मुद्दे पर देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। नड्डा ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के एक नेता को खुद सिलेंडर की जमाखोरी करते हुए पकड़ा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुश्किल समय में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। नड्डा ने खड़गे को टोकते हुए कहा कि शून्यकाल में बोलने की समय सीमा 3 मिनट है, जिसका पालन विपक्ष के नेता को भी करना चाहिए। देश में गैस की यह कमी मुख्य रूप से ईरान-इजरायल संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मार्ग बाधित होने से हुई है। जहां सरकार का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है और वैकल्पिक देशों (रूस, अमेरिका, कनाडा) से आयात की कोशिशें जारी हैं, वहीं विपक्ष इसे सरकार की अदूरदर्शिता बता रहा है।

बंगाल में चुनाव से पहले मुख्य सचिव-डीजीपी को हटाया गया

***कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत 6 अधिकारी बदले**
***आयोग बोला- वे अफसर चुनाव से दूर रहेंगे**

नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के दूसरे ही दिन चुनाव आयोग ने 6 अफसरों का तबादला कर दिया। आयोग ने पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता को डीजीपी बनाया है। वहीं, आयोग ने राय की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटा दिया है। उनकी जगह 1993 बैच के आईएएस तुषांत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। सुप्रतिम सरकार की जगह अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। साथ ही राय के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा की जगह 1997 बैच की आईएएस अफसर सौमित्रा घोष को गृह सचिव बनाया गया है। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

नटराजन रमेश बाबू को सुधार सेवा महानिदेशक बनाया गया है। अजय मुकुंद रानाडे को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और आईजीपी (कानून-व्यवस्था) का पद दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, उन्हें चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी चुनाव से जुड़े पद पर तैनात नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने रविवार को बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। बंगाल की 294 सीटों पर 2 फेज में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। 4 मई को रिजल्ट आएगा। चुनाव आयोग ने आदेश में कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद वह लगातार प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। इसी क्रम में यह फैसला लिया गया है। आयोग का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक बदलाव किए जा रहे हैं।

बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए के सभी पांचों उम्मीदवार जीते, महागठबंधन के 37 विधायकों ने ही किया वोट

पटना । राज्यसभा चुनाव में बिहार से एनडीए के सभी 5 उम्मीदवारों को जीत मिल गई है. महागठबंधन को विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा चुनाव में भी हार झेलनी पड़ी है. मालूम हो कि बिहार से राज्यसभा के खाली हुए 5 सीटों के लिए एनडीए बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) प्रमुख नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री राम नाथ ठाकुर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा (दोनों राज्यसभा के मौजूदा सदस्य) और भाजपा के शिवेश कुमार को उतारा था. इन सभी को जीत मिल गई है. बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव में एनडीए के 202 विधायकों ने वोटिंग किया. महागठबंधन के 37 विधायकों ने ही वोटिंग किया है. महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस

विधायक मनोज विश्वास, कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह और राजद विधायक फैसल रहमान वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे.

243 विधासभा वाले बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव

मालूम हो कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं. वहां राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव हुआ है. लेकिन 5 सीटों के लिए 6 कैंडिडेट मैदान में थे. ऐसे में यहां के राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर हर किसी नजर थी. बिहार में एनडीए के 202 विधायक है. वहीं, महागठबंधन के 35 विधायक हैं.

असल मुकाबला पांचवीं सीट को लेकर था

विधायकों के संख्याबल के जरिए यह साफ था कि एनडीए को राज्यसभा की 4 सीटों पर तो आसानी से जीत मिल जाएगी. असल मुकाबला पांचवीं सीट के लिए था. बिहार में राज्यसभा के एक उम्मीदवार को जीत के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत थी. इस लिहाज से एनडीए को 4 सीटों की जीत के लिए 164 विधायक लगे. इसके बाद एनडीए के पास 38 विधायक थे 5वीं सीट जीतने के लिए उसे 3 और विधायकों का समर्थन चाहिए था. जिसे एनडीए ने आसानी से पा लिया.

भारतीय नौसेना ने होर्मुज के पास तैनात किए दो युद्धपोत

भारत ने सोमवार को कहा कि खाड़ी में कम से कम 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज और 611 भारतीय नाविक अभी भी मौजूद हैं. भारत इसको लेकर ईरान से बातचीत कर रहा है.

तेल अवीव/तेहरान। अमेरिका-इजराइल और ईरान में जारी जंग के बीच भारत ने होर्मुज स्ट्रेट के पास अपने दो युद्धपोत तैनात किए हैं। एनआईए ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारतीय नौसेना के ये टास्क फोर्स जहाज तेल और गैस लेकर भारत आने वाले व्यापारी जहाजों और टैंकरों को सुरक्षा देंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें हर तरह की सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। तीन सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान ने भारत से फरवरी में जब्त किए गए तीन टैंकरों को छोड़ने का अनुरोध किया है. ये टैंकर भारतीय ध्वज वाले या भारत जाने वाले जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से खाड़ी से सुरक्षित निकालने के लिए चल रही बातचीत का हिस्सा थे. भारतीय अधिकारियों ने भारतीय जलक्षेत्र के पास ईरान से जुड़े इन तीन टैंकरों को इस आरोप में जब्त किया था कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाई या बदली थी और वे समुद्र में अवैध जहाज-से-जहाज हस्तांतरण में शामिल थे.

ईरान की और क्या डिमांड

एक ईरानी अधिकारी के अनुसार, तेहरान ने कुछ दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की भी मांग की है. सूत्रों ने बताया कि सोमवार को नई दिल्ली स्थित ईरान के राजदूत ने भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की. मामले की संवेदनशीलता के कारण सूत्रों ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया. भारत के विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास और ईरान के विदेश मंत्रालय ने रॉयटर्स के टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया. भारतीय अधिकारियों के अनुसार, ईरान ने हाल ही में दो भारतीय द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) टैंकरों को जलडमरूमध्य से गुजरने की

अनुमति दी, जिनमें से एक सोमवार को पश्चिमी भारत लौट आया. ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरूमध्य के दोनों ओर यातायात लगभग ठप हो गया है. भारतीय जहाजों के लिए मार्ग सुनिश्चित करने वाली वार्ता के बारे में पूछे जाने पर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोमवार को कहा कि हाल की गतिविधियां आपसी सहयोग और बातचीत के इतिहास को दर्शाती हैं. उन्होंने दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कोई लेन-देन नहीं हुआ है.

भारत के कितने जहाज फंसे

फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों की शुरुआत के बाद से, तेहरान ने पूरे क्षेत्र में हमले किए हैं, जिनमें होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमले भी शामिल हैं, जिनमें तीन भारतीय नाविक मारे गए और एक लापता है. भारत ने सोमवार को कहा कि खाड़ी में कम से कम 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज और 611 भारतीय नाविक अभी भी मौजूद हैं. एक भारतीय सूत्र ने बताया कि इनमें से छह जहाजों में एलपीजी भरी हुई थी और देश खाना पकाने के ईंधन की कमी को दूर करने के लिए इन जहाजों को पहले रवाना करने के लिए उत्सुक था. भारत के कुल एलपीजी आयात का लगभग 90फीसदी खाड़ी देशों से आता है.

होर्मुज से भारतीय जहाज पास कराने के बदले अपने जब्त टैंकर वापस मांग रहा ईरान- रायटर्स सूत्र

कैसे पकड़े गए थे ईरानी टैंकर

भारतीय अधिकारियों ने एमस्काल्ट स्टार, अल नाफजिया और स्टेलर रूबी नामक टैंकरों को जब्त किया था. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पहचान और गतिविधियों को छिपाया या बदला था और वे अवैध जहाज-से-जहाज हस्तांतरण में शामिल थे.

स्टेलर रूबी ईरानी ध्वज वाला जहाज है, जबकि अन्य दो जहाज निकारगुआ और माली के ध्वज वाले हैं. भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 15 फरवरी को दर्ज कराई गई और रॉयटर्स द्वारा देखी गई एक पुलिस शिकायत में कहा गया है कि एमस्काल्ट स्टार भारी ईंधन तेल की तस्करी में शामिल थी, जिसे अल नाफजिया और बिटुमेन को स्टेलर रूबी को हस्तांतरित किया गया था. ये तीनों जहाज वर्तमान में मुंबई के तट पर खड़े हैं. जब्ती के समय के अलावा, ईरानी सरकारी मीडिया ने नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के हवाले से कहा कि जब्त किए गए तीनों टैंकरों का कंपनी से कोई संबंध नहीं है.

जुगिंदर सिंह बराड़, जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका ईरानी तेल परिवहन में मदद करने वाले जहाजी बेड़े को चलाने का आरोप लगाता है, ने कहा कि वह भारत द्वारा जब्त किए गए तीनों जहाजों के सलाहकार थे और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था. उन्होंने रॉयटर्स को फोन पर बताया, हम बिटुमेन का परिवहन कर रहे थे और इसमें कुछ भी अवैध नहीं है. मेरे जहाज 40 दिनों से वहां हैं और मुझे नुकसान हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें टैंकरों को लेकर किसी भी बातचीत की जानकारी नहीं है.